भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3109

जिसका उत्तर 11 मार्च, 2026 को दिया जाना है ।

20 फाल्गुन, 1947 (शक)

सरकारी ईमेल खातों का एनआईसी से "ज़ोहो" में स्थानांतरण

3109. श्री दीपक अधिकारी (देव):
श्रीमती माला रायः

क्या **इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का एनआईसी से एक मिलियन ई-मेल खाते (सरकारी) निजी कंपनी "ज़ोहो" को संचालन के लिए सौंपने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ग) सरकार से सेवा प्रदाता के रूप में "ज़ोहो" को कितनी धनराशि मिलने की अपेक्षा है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ग):** भारत सरकार शासन, अंतर-मंत्रालयी समन्वय और नागरिक-केंद्रित सेवा प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मेल को आधिकारिक संचार के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में मान्यता देती है। विरासत में प्राप्त ई-मेल अवसंरचना को आधुनिक बनाने और विस्तार क्षमता, सुरक्षा और सहयोग क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकार ने आधिकारिक ई-मेल प्रणाली को एक सुरक्षित, क्लाउड-आधारित प्लेटफॉर्म में अपग्रेड करने का कार्य शुरू किया है।

उन्नत ई-मेल समाधान (नया प्लेटफार्म) जोहो कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसे एक खुली और प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चुना गया है। यह संलग्नता स्पष्ट रूप से परिभाषित तकनीकी, सुरक्षा और सेवा-स्तर की आवश्यकताओं पर आधारित है। इसके बाद लगभग 16.68 लाख सक्रिय आधिकारिक ईमेल खातों को उन्नत ई-मेल समाधान में स्थानांतरित कर दिया गया है। हालांकि, सरकारी डेटा का स्वामित्व और नियंत्रण हर समय भारत सरकार के पास बना रहता है।

सेवा प्रदाता को भुगतान खुली प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया के माध्यम से अंतिम रूप दी गई दरों के अनुसार होता है। प्रति ई-मेल खाते की दर पारदर्शी बोली के माध्यम से निर्धारित की गई है, जिससे सार्वजनिक निधियों के लिए लागत-दक्षता और मूल्य सुनिश्चित किया जा सके। कुल व्यय प्रावधान किए गए खातों की संख्या और सरकारी मानदंडों के अनुसार निष्पादित संविदा की शर्तों पर आधारित है।

****